प्रवर्तकों को देनी होगी पासपोर्ट की जानकारी

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। कम्पनी मामलों का मंत्रालय (एम.सी.ए.) कम्पनियों के सभी प्रवर्तकों और निदेशकों को कम्पनी पंजीयक (आर.ओ.सी.) के पास उनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारियां अनिवार्य तौर पर मुहैया करवाने के लिए कह सकता है। इस कदम का मकसद कम्पनियों के प्रवर्तकों और निदेशकों को देश से भागने से रोकना है। इस बारे में मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ''हम प्रवर्तकों और निदेशकों को उनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारियां दर्ज करवाने के लिए कह सकते हैं। हम इसे लेकर वाकई गंभीर हैं।'' हाल में पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) के साथ फर्जीवाड़ा करने के बाद हीरा कारोबारी नीरव मोदी देश से फरार हो गया था। मोदी और उनकी कम्पनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं। इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या भी बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भाग गया था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही इस पहल पर विचार किया जा रहा है। आर्थिक अपराध करने के बाद फरार होने वाले ऐसे लोगों पर नकेल कसने और उनकी परिसंपत्तियां जब्त करने के लिए सरकार भगौड़ा आर्थिक अपराध कानून लेकर आई है। इस बीच कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस) की मदद से कम्पनियों में फर्जीवाड़े का पता लगाने की योजना पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। मंत्रालय ने इस परियोजना पर 1.2 अरब रुपए लागत आने का अनुमान लगाया है। हालांकि इस परियोजना के लिए आई सबसे कम बोली भी परियोजना लागत से 100 प्रतिशत अधिक थी। शैल यानी मुखौटा कम्पनियों को दबोचने के लिए मंत्रालय ने पूर्व चेतावनी प्रणाली तैयार करने की योजना बनाई थी। इसके तहत सॉफ्टवेयर के जरिए कम्पनियों पर नजर रखी जाएगी और किसी तरह की असामान्य गतिविधि नजर में आते ही यह तत्काल आर.ओ.सी. को सूचित कर देगा।

सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता पहली तिमाही में 34% बढ़ी

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। देश की सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 की पहली तिमाही में यह 34 प्रतिशत बढ़कर 3,269 मेगावाट रही। पिछले साल 2017 की चौथी तिमाही में 2,448 मेगावाट क्षमता स्थापित की गयी थी। वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परामर्श फर्म मरकॉम कम्युनिकेशंस इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। फर्म ने बयान में कहा कि सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिहाज से 2018 की पहली तिमाही सबसे अच्छी रही। इस दौरान 3,269 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई जो 2017 की चौथी तिमाही में स्थापित क्षमता 2,448 मेगावाट से 34 प्रतिशत अधिक है। यह 2017 की पहली तिमाही के आंकड़े से भी अधिक है। 2017 की पहली तिमाही में 2,991 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गयी थी। परियोजनाओं के पूरे होने के कारण तेजी रही। ये परियोजनाएं पिछली तिमाही में चालू होनी थी लेकिन ग्रिड कनेक्शन की समस्या के कारण इसमें देरी हुई। इसमें कहा गया है कि यह पहली तिमाही है जिसमें 3,000 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई और यह लगातार पांचवी तिमाही है जिसमें कम से कम 2,000 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई। बयान में कहा गया है कि 2018 की पहली तिमाही के अंत में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 22,800 मेगावाट पहुंच गई।

एचडीएफसी बैंक के एटीएम से नहीं कर पाएंगे ट्रांजेक्शन

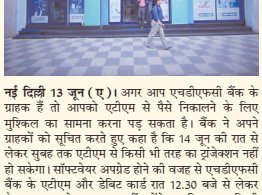

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित करते हुए कहा है कि 14 जून की रात से लेकर सुबह तक एटीएम से किसी भी तरह का ट्रांजेशन नहीं हो सकेगा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने की वजह से एचडीएफसी बैंक के एटीएम और डेबिट कार्ड रात 12.30 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक काम नहीं करेंगे। इसलिए आप किसी भी तरह का ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर एटीएम से कैश नहीं निकाल सकेंगे। बैंक ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वो अपने सभी बैंक से जुड़े कार्य रात 12 बजे से पहले ही कर लें, ताकि कोई दिक्कत न हो। बता दें कि 12 जून को भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के चलते एटीएम से किसी भी तरह का ट्रांजेशन नहीं हुआ। बता दें कि एचडीएफसी बैंक ने अपना लोन महंगा कर दिया है। बैंक ने एमसीएलआर में 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। बैंक की एक साल की एमसीएलआर की दर अब 8.40 फीसदी होगी। इसी तरह 2 साल की दर 8.55 फीसदी होगी। इससे एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों का होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा।

सरकार ने रिकॉर्ड 3.5 करोड़ टन गेहूं की खरीद की

भंडार केंद्र किराए पर लेने की योजना

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। सरकार इस साल गेहूं की खरीद रिकॉर्ड 3.5 करोड़ टन से ऊपर पहुंचने के साथ उत्तर और मध्य भारत में मॉनसून आने से पहले अनाज के भंडारण के लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधा किराए पर लेने की योजना बना रही है। गेहूं और चावल की खरीद की खरीद तथा वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सरकार की नोडल एजेंसी है। एफसीआई ने राज्य की एजेंसियों के साथ मिलकर अच्छी पैदावार के साथ विपणन वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) में रिकॉर्ड 3.52 करोड़ टन गेहूं की खरीद की है। इन एजेंसियों की संयुक्त रूप से भंडारण 8 करोड़ टन है।

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''काफी भंडार है। हम गेहूं का भंडारण के लिए व्यवस्था करेंगे। हम विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम भंडारण सुविधा किराए पर लेने के बारे में सोच रहे हैं।'' रिकॉर्ड खरीद के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं की कुछ मात्रा खुले में ढककर रखी गई है। बारिश शुरू होने से पहले इसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जरूरत है। एफसीआई के आंकड़े के अनुसार गेहूं की कुल खरीद इस साल के लिए निर्धारित 3.2 करोड़ टन के लक्ष्य से पार कर गई है। पंजाब में गेहूं की खरीद आलोच्य विपणन वर्ष में बढ़कर 1.27 करोड़ टन पहुंच गई जो पिछले साल 1.17 करोड़ टन थी। वहीं हरियाणा में खरीद 87 लाख टन रही जो पिछले साल 74.3 लाख थी। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद बढ़कर 72.8 लाख टन पहुंच गई जो एक साल पहले इसी अवधि में 67.2 लाख टन थी। पंजाब और हरियाणा में गेहूं खरीद की प्रक्रिया पूरी हो गई है जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जारी है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2017-18 (जुलाई-जून) में गेहूं का उत्पादन 9.86 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

वीजा ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर चार्ज 95 प्रतिशत घटाया

बेंगलुरु 13 जून (ए.)। देश में सबसे बड़े कार्ड पेमेंट नेटवर्क वीजा ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर चार्ज में भारी कमी की है। इससे वीजा के साथ जुड़ने वाले छोटे मर्चेंट और कस्टमर्स की संख्या में बढ़ोतरी होने से डिजिटल पेमेंट्स मार्केट बढ़ेगा। वीजा ने बताया कि उसने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर चार्ज में 95 पर्सेंट तक की कमी की है। 2,000 रुपये से कम की ट्रांजैक्शंस पर चार्ज सबसे अधिक घटाया गया है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया, कंज्यूमर और मर्चेंट की सभी कैटेगरी में डिजिटल पेमेंट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए वीजा ने अपनी डेटा प्रोसेसिंग फीस में कमी की है। इससे सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।ए अनुमान के अनुसार, देश में कार्ड ट्रांजैक्शंस में वीजा का मार्केट शेयर 40 पर्सेंट से अधिक है।

कार्ड के इस्तेमाल के लिहाज से डेबिट कार्ड की हिस्सेदारी 96 पर्सेंट की है, लेकिन कार्ड पेमेंट की वैल्यू में क्रेडिट कार्ड का योगदान 51 पर्सेंट है। देश में केवल 3.7 करोड़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है, जबकि डेबिट कार्ड की संख्या 86.1 करोड़ है। एक जुलाई से कार्ड जारी करने वाले बैंक पर लागू वीजा के चार्ज 2,000 रुपये से कम की ट्रांजैक्शंस पर घटकर 15 पैसे और अधिक वैल्यू की पेमेंट पर 1.5 रुपये हो जाएंगे। अभी इन पर 2.99 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का समान रेट लगता है।

मर्चेंट को हासिल करने वाले बैंकों पर 2,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन के लिए वीजा ने चार्ज 45 पैसे से घटाकर 15 पैसे कर दिया है। कार्ड इश्यू करने वाले और मर्चेंट एक्वायर करने वाले बैंक आमतौर पर ये चार्ज मर्चेंट्स से लेते हैं। हालांकि, वीजा ने सर्विस फीस को ट्रांजैक्शन की रकम के 0.035 पर्सेंट से बढ़ाकर 0.055 पर्सेंट कर दिया है।

एक सीनियर बैंकर ने बताया, मर्चेंट और बैंक कम वैल्यू की ट्रांजैक्शंस के लिए लगभग शून्य चार्ज देंगे। इस कदम के साथ बैंकों के लिए छोटी दुकानों पर टर्मिनल लगाना और डेबिट कार्ड पेमेंट को प्रोत्साहन देना अधिक आकर्षक हो जाएगा। नए रेट केवल डोमेस्टिक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए लागू होंगे।

देश में शुरू हुई कार्ड पेमेंट स्कीम रुपे के कम रेट्स भी वीजा की ओर से चार्ज घटाने का एक कारण हैं।

पतंजलि को पछाड़ अडानी समूह ने लगाई रुचि सोया के लिए सबसे बड़ी बोली

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। अरबपति कारोबारी गौतम अडाणी के अडाणी समूह ने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रुचि सोया के अधिग्रहण के लिए 6,000 करोड़ रुपए की पेशकश की है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कंपनी अधिग्रहण के लिए सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव प्रर्वित पतंजलि आयुर्वेद ने करीब 5,700 करोड़ रुपए की बोली लगाई है।

हालांकि, स्विस चैलेंज विधि के तहत चल रही नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत पतंजलि के पास पेशकश का मिलान करने का अधिकार होगा। रुचि सोया के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने पतंजलि और अडाणी विलमर द्वारा दाखिल बोली को खोला। सीओसी ने रुचि सोया की परिसंपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए स्विस चैलेंज विधि का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया

है। बोली के मूल्य को लेकर पतंजलि के प्रवक्ता ने कोई जानकारी नहीं दी है।

पतंजलि के प्रवक्ता एस के तिजारावाला ने कहा, हम हैरान हैं और सीओसी से जानकारी मांगेंगे। सूत्रों ने कहा कि कर्जदाता रुचि सोया के अधिग्रहण के लगाई गई शुरुआती बोली से खुश नहीं है। इस दौरान पतंजलि 4,300 करोड़ रुपए की पेशकश के साथ सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरी थी। अडाणी ने 3,300 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। रुचि सोया पर बैंकों का करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज है। स्विस चैलेंज विधि के अंतर्गत, अडाणी को पेशकश का एक और मौका मिलेगा यदि पतंजलि उसकी 6,000 करोड़ रुपए की पेशकश के बराबर या उससे अच्छी बोली लगाती है। पतंजलि और अडाणी के अलावा इमामी एग्रोटेक और गोदरेज एग्रोवेट ने भी रुचि सोया के अधिग्रहण की इच्छा जताई थी।

वोडाफोन एप पर गेम खेलकर जीत सकते हैं एपल आईपैड

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। फुटबॉल को लेकर लोगों में दीवानगी को बढ़ाने के लिए वोडाफोन अपने ग्राहकों के लिए एक ईनामी पेशकश लेकर आया है जिसके तहत ग्राहक 'माय वोडाफोन एप' पर एक गेम खेलकर आसानी से आईपैड मिनी जीत सकते हैं।

ऐसे जुटाएं ज्यादा स्कोर: वोडाफोन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उपभोक्ता को एप पर गेम खेलना होगा और अंक (प्वाइंट) स्कोर करने होंगे। इसका आयोजन 11 जून से 15 जुलाई 2018 के बीच किया जाएगा। वोडाफोन के 'गैट-सैट-गोल' प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एप पर गोल करके अंक जुटाने होंगे। रिचार्ज और बिलों का भुगतान करके ज्यादा स्कोर या अंक जुटाए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा अंक एकत्र करने वाले को बंपर पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। बंपर पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए का यात्रा वाउचर भी मिलेगा।

फीफा के इस सत्र को रोचक बनाना: कंपनी का कहना है कि 'माय वोडाफोन एप' पर इस अनूठे प्रस्ताव के साथ वोडाफोन इंडिया का उद्देश्य अपने डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए फीफा के इस सत्र को कई गुना रोचक बनाना है।

अटल टिंकरिंग लैब के लिए 3,000 अतिरिक्त स्कूलों का चयन

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। नीति आयोग ने बच्चों में अनुसंधान एवं उद्यमिता बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई योजना अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्थापित करने के लिए 3,000 और स्कूलों को चुना है। इसके साथ एटीएल स्कूलों की संख्या बढ़कर 5,441 हो गई है। साथ ही आयोग ने कहा है कि जल्दी ही अटल इनोवेशन मिशन की पहुंच देश के सभी जिलों में होगी। नीति आयोग के बयान के अनुसार चुने गए स्कूलों को अगले 5 साल में 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नीति आयोग ने यह भी कहा है कि जल्दी ही देश के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन तथा शिक्षा-दीक्षा व्यवस्था में बड़ा रूपांतरण आएगा। अटल इनोवेशन मिशन के प्रबंध निदेशक रामनाथन रमणन ने कहा, ''इन 3,000 अतिरिक्त स्कूलों के आने से एटीएल कार्यक्रम का दायरा व्यापक होगा। नवप्रर्वतन गतिविधियों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी और युवा नवप्रर्वतकों के पास उडी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट आफ थिंग्स तथा माइक्रोप्रोसेसर्स जैसी प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध होगी।''

2025 तक रेलवे की आमदनी डबल करना चाहते हैं गोयल

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे की आमदनी 2025 तक दोगुनी करके 4 लाख करोड़ रुपये करने और उसे तब तक मुनाफे में लाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेलवे करीब 9 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। गोयल ने इकनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया, हमारा लक्ष्य रेलवे को मुनाफे में लाना है ताकि इसे सरकार से वित्तीय मदद की जरूरत न पड़े। हम 2025 तक रेलवे की आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं।

गोयल ने कहा कि उनका ध्यान सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिक नेटवर्क को बढ़ाने, कंजस्टेड एरिया में रेलवे लाइनें बढ़ाने और मौजूदा एसेट्स का इस्तेमाल बढ़ाकर रेलवे की क्षमता में सुधार लाने पर है। उन्होंने बताया, रेलवे की लागत कम करना सबसे बड़ी बात है। अगर हम अपने नेटवर्क के बड़े हिस्से का विद्युतीकरण करते हैं तो बड़ी आसानी से सिर्फ डीजल पर 15 हजार करोड़ की बचत कर सकते हैं। रेलवे ने पांच साल में अपनी ज्यादातर लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना बनाई है, जिससे वह अहम रूट्स पर डीजल इंजन के बदले बिजली के इंजन का इस्तेमाल कर पाएगा। गोयल ने यह भी बताया, गोल्डेन क्वॉड्रिलैटरल रूट पर आधुनिक सिग्नल सिस्टम लगाकर हम रेलवे लाइन की क्षमता में 50 पर्सेंट की बढ़ोतरी कर सकते हैं। अभी इन लाइंस के जरिये 58 पर्सेंट माल की ढुलाई हो रही है। उन्होंने कहा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करके हम आमदनी में कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे हमें छोटे रूट पर अधिक ट्रेनें चलाने में मदद मिलेगी। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ा जाना है। गोयल ने बताया कि इस पर काम तय टाइमलाइन के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मेट्रो शहरों के बीच चार-पांच और ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर विचार कर रही है। इकनॉमिक टाइम्स ने खबर दी थी कि अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जमीन खरीदने संबंधी दिक्कतों के चलते कुछ बाधाएं आई हैं। गोयल अभी वित्त मंत्रालय का भी कामकाज देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 2019 लोकसभा चुनाव में 350 सीटों पर जीत हासिल करेगा। जब उनसे रेलवे के तहत आने वाली कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि RITES और IRCON की लिस्टिंग जल्द होगी। उन्होंने कहा कि सरकार रेलवे में निवेश बढ़ाने के लिए नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। गोयल ने यह भी बताया कि मार्च 2019 से पहले 68 स्टेशनों का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को निजी कंपनियों के लिए आकर्षक बनाने के उपायों पर भी काम चल रहा है।

धोखाधड़ी मामलों के लिए हर बैंक शाखा की निगरानी असंभव

नई दिल्ली 13 जून (ए.)। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने मंगलवार को कहा कि केन्द्रीय बैंक के पास उस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है जैसी नीरव मोदी ने की और बैंकिंग नियामक के लिए सभी बैंक शाखाओं की निगरानी कर पाना असंभव है।

उठाए जा रहे कई कदम

सूत्रों के अनुसार पटेल ने कांग्रेस सदस्य एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थायी संसदीय समिति को दिए लिखित बयान में यह बात कही। उन्होंने लिखा है कि देश में 1.63 लाख से अधिक बैंक शाखाएं हैं, जिससे केन्द्रीय बैंक के लिए दैनिक आधार पर नीरव मोदी जैसे मामलों की निगरानी करना असंभव है। उन्होंने संसदीय समिति का आश्वस्त किया कि बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में नीरव मोदी जैसे मामले नहीं हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्या से जल्द ही निजात पा लिया जाएगा।

एनपीए मामले में हो रहा सुधार

सूत्रों ने कहा कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में पटेल ने समिति से कहा कि इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी

कोर्ड के लागू होने के बाद एनपीए के मामले में सुधार होने लगा है। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने जोखिम वाले ऋण में हो रही बढोतरी और कई सरकारी बैंकों की स्थिति पर भी चिंता जताई। सूत्रों के अनुसार, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से नोटबंदी के दौरान जमा हुए नोटों के बारे में भी पूछा जिस पर उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने नोट गिनती करने वाली नई मशीनों के आर्डर दिए गए क्योंकि पुरानी मशीने या कर्मचारी इतने अधिक नोटों की गिनती पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

खरीदी जा रही है नई मशीनें

नई मशीनें खरीदी जा रही है जो नोटों की चुटकी बजाते गिनती करने और नकली नोट अलग करने में भी सक्षम हैं। इस समिति में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद सदस्य हैं। सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे और रत्तन लाल कटारिया, बीजू जनता दल के बी मेहताब, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेम दास राय, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और दिनेश त्रिवेदी तथा कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।